समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Tuesday, 22 September 2026

नीतीश कुमार की सैलरी और पेशंन : जाने बिहार के सीएम को मिलेगी कितनी सुविधाएं और MLA को मिलने वाली भत्ते

Publisher

Published on 20 Nov 2025

बिहार के राजनीति प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के दसवीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सीएम पद संभालने के साथ ही उनके वेतन, पेंशन और अन्य सुविधाओं को लेकर लोगों में खास उत्सुकता देखने को मिल रही है।

मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को हर महीने लगभग 2.5 लाख रुपये की सैलरी मिलेगी। इस सैलरी में उनके सरकारी आवास, दफ्तर, सुरक्षा, परिवहन, बिजली-पानी सहित विधायक से जुड़ी अन्य सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री को विशेष भत्ते और सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं, जो उन्हें अपने पद की जिम्मेदारियों के निर्वहन के दौरान सुविधा और आराम प्रदान करती हैं।

बिहार के मंत्रियों को हर महीने 65,000 रुपये का वेतन और 70,000 रुपये का क्षेत्रीय भत्ता मिलता है। यह भत्ता उनके कार्य क्षेत्र और जनसंपर्क से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए दिया जाता है। मंत्रियों के पास भी मुख्यमंत्री की तरह सरकारी आवास, दफ्तर, वाहन और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होती है।

MLA यानी विधायक को भी राज्य सरकार से अलग-अलग भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं। इसमें सरकारी आवास, परिवहन भत्ता, चिकित्सा सुविधाएं, दैनिक यात्रा भत्ता और अन्य सरकारी सुविधाएं शामिल हैं। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि विधायक अपनी जनता की सेवा करते समय आर्थिक बाधाओं से मुक्त रह सकें और राज्य के विकास में अपना योगदान दे सकें।

नीतीश कुमार की सैलरी और पेंशन की जानकारी को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें पेंशन का भी अधिकार होगा। यह पेंशन उनके सेवा निवृत्त होने के बाद उनके जीवनयापन और सरकारी सेवा में योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रदान की जाती है। पेंशन की रकम और अन्य लाभ राज्य सरकार के नियमों और बजट पर निर्भर करते हैं।

राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सैलरी और भत्ते सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होते, बल्कि यह

उनके सार्वजनिक दायित्वों और कार्यों को सुचारू रूप से निभाने के लिए अनिवार्य होते हैं। नीतीश कुमार जैसे अनुभवी नेता के लिए यह वेतन और सुविधाएं उनके कार्य क्षेत्र और जनता की सेवा में आने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मानी जाती हैं।

साथ ही, राज्य सरकार द्वारा विधायक और मंत्री को मिलने वाली सुविधाओं में पारदर्शिता बनाए रखना भी आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक धन का उपयोग सही तरीके से हो और जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो। बिहार में पिछले कुछ वर्षों में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सैलरी और भत्तों में बढ़ोतरी समय-समय पर की जाती रही है, ताकि यह उनके कार्य और जिम्मेदारियों के अनुपात में सही रहे।

नीतीश कुमार की सैलरी और पेंशन को लेकर चर्चा केवल वित्तीय लाभ तक सीमित नहीं है। यह जनता और मीडिया के लिए यह जानना भी जरूरी है कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियों की प्रकृति कितनी व्यापक है और इस पद पर काम करने के लिए उन्हें किन-किन संसाधनों की आवश्यकता होती है। मुख्यमंत्री को राज्य के विकास, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, और विभिन्न कल्याण योजनाओं की निगरानी करनी होती है। इसके लिए उन्हें पर्याप्त बजट, कर्मचारी और संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं।

बिहार के मुख्यमंत्री पद पर 10वीं बार नीतीश कुमार के शपथ लेने के बाद यह साफ है कि उनकी नीतियों और प्रशासनिक कार्यशैली पर राज्य की जनता की निगाहें टिकी होंगी। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि वे अपनी सैलरी, भत्तों और पेंशन का किस तरह से जनता की भलाई और राज्य के विकास में उपयोग करते हैं।

इस तरह, नीतीश कुमार की सैलरी, पेंशन और सरकारी सुविधाएं केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि उनके पद की गरिमा और जिम्मेदारी के प्रतीक के रूप में भी देखी जाती हैं। बिहार की जनता के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि उनके चुने हुए नेता को किस प्रकार के संसाधन मिल रहे हैं और उसका उपयोग राज्य के विकास और जनता की भलाई के लिए हो रहा है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.